



Neutral Citation No. - 2026:AHC:60308-DB

उच्च न्यायालय इलाहाबाद

प्रथम अपील दोषपूर्ण संख्या - 244/2026

अमित बाजपेयीअपीलार्थी

बनाम

श्रीमती रश्मिप्रत्यर्थी

अपीलार्थी के अधिवक्ता: भविष्य शर्मा, सर्वेश कुमार दुबे

प्रत्यर्थी के अधिवक्ता:

न्यायालय संख्या - 2

माननीय न्यायमूर्ति अतुल श्रीधरन,

माननीय न्यायमूर्ति विवेक सरन,

सिविल प्रकीर्ण विलंब क्षमापना प्रार्थना पत्र संख्या 1/2026

1. श्री आलोक रंजन त्रिपाठी ने प्रत्यर्थी की ओर से वकालतनामा दाखिल किया है, जिसे अभिलेख पर लिया जाता है।
2. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता श्री भविष्य शर्मा और प्रत्यर्थी के विद्वान अधिवक्ता श्री आलोक रंजन त्रिपाठी को सुना।
3. यह 694 दिनों के विलंब को क्षमा करने का प्रार्थना पत्र है। आक्षेपित आदेश दिनांक 05.03.2024 है, जो अपीलार्थी द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 340 के तहत विद्वान विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत एक प्रार्थना पत्र में पारित किया गया था। विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र को खारिज कर दिया गया था और उसके बाद दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 341 के तहत वैधानिक अपील इस न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश के समक्ष वर्ष 2024 से 2026 तक लंबित रही, जिसके पश्चात विद्वान एकल न्यायाधीश ने परिवार न्यायालय अधिनियम, 1984 की धारा 19 का परिशीलन करने के उपरांत यह राय व्यक्त की कि उक्त मामले की सुनवाई इस न्यायालय द्वारा की जानी चाहिए।
4. परिस्थितियों के दृष्टिगत, यह न्यायालय संतुष्ट है कि 694 दिनों के विलंब को पर्याप्त रूप से स्पष्ट किया गया है और यह विलंब इस न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश के समक्ष मामला लंबित होने के कारण हुआ। तदनुसार, विलंब क्षमा किया जाता है।

सिविल प्रकीर्ण छूट प्रार्थना पत्र

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



5. आक्षेपित निर्णय और आदेश दिनांक 05.03.2024 की डिक्री की प्रति और उक्त आक्षेपित निर्णय के फोलियो को दाखिल करने से छूट दी जाती है।
6. छूट प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

प्रथम अपील पर आदेश

7. मामले के गुण-दोष पर पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुना।
8. जिस आदेश के विरुद्ध अपील की गई है वह दिनांक 05.03.2024 का है। यह अपीलार्थी द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 340 के तहत प्रस्तुत एक प्रार्थना पत्र को तय करते हुए पारित किया गया था। विद्वान विचारण न्यायालय के समक्ष मुख्य मामला अपीलार्थी (पति) और प्रत्यर्थी (पत्नी) के बीच है। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 340 के तहत प्रार्थना पत्र में आरोप यह था कि इस न्यायालय के समक्ष प्रत्यर्थी ने अपने लिखित बयान में गलत तरीके से कहा है कि वह एक गृहिणी है, जबकि वह एक योग्य फिजियोथेरेपिस्ट है और जयराम अस्पताल से जुड़ी हुई थी तथा फिजियोथेरेपिस्ट के रूप में निजी प्रैक्टिस भी कर रही थी। उक्त आदेश एकपक्षीय पारित किया गया है क्योंकि विद्वान विचारण न्यायालय ने सही राय बनाई कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 340 के तहत कार्यवाही में प्रत्यर्थी / भावी अभियुक्त को सुनना आवश्यक नहीं होगा।
9. हालांकि, विद्वान विचारण न्यायालय ने यह विचार व्यक्त किया कि अपीलार्थी अपने आरोपों को साबित करने में सक्षम नहीं रहा है। दूसरे शब्दों में, विद्वान विचारण न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचा कि यद्यपि अपीलार्थी सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत प्राप्त दस्तावेजों के आधार पर यह स्थापित करने में सक्षम रहा कि प्रत्यर्थी एक योग्य फिजियोथेरेपिस्ट थी, किंतु वह ऐसा कोई दस्तावेज प्रस्तुत करने में असमर्थ रहा कि वह जयराम अस्पताल में सेवा में थी और वह फिजियोथेरेपिस्ट के रूप में निजी प्रैक्टिस के माध्यम से भी कमा रही थी। यह उल्लेख करना भी आवश्यक है कि जब उक्त प्रार्थना पत्र तय किया गया था, तब मुख्य मामला / विचारण लंबित था और उस मामले में अंतिम आदेश पारित नहीं हुआ था। हालांकि, अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि प्रत्यर्थी का प्रतिपरीक्षण पहले ही किया जा चुका था।
10. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने अपनी अपील के पैराग्राफ संख्या 18 की ओर इस न्यायालय का ध्यान आकर्षित किया है, जिसमें उन्होंने प्रत्यर्थी द्वारा प्रतिपरीक्षण में दी गई गवाही के एक अंश का उल्लेख किया है, जहाँ उसने कहा है कि यह कहना गलत है कि जयराम अस्पताल के अलावा वह कहीं और प्रैक्टिस कर रही है। यह भी स्पष्ट रूप से कहा जाना चाहिए कि अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने वास्तव में विद्वान विचारण न्यायालय के समक्ष प्रत्यर्थी द्वारा दी गई गवाही की ओर न्यायालय का ध्यान आकर्षित किया है, जो अपील के पृष्ठ संख्या 121 पर है। गवाही का अंश निम्नानुसार है:
"यह कहना गलत है कि मैं जयराम हॉस्पिटल के अलावा कहीं प्राइवेट प्रैक्टिस कर रही हूँ। मैंने कभी कोई कोई नौकरी नहीं की है। मैंने अपने साक्ष्य शपथ पत्र की धारा 21 में लिखा है कि विपक्षी व उसके परिवार वालों के षड्यंत्र के कारण नौकरी छूट गयी है।"
11. इस प्रकार, प्रत्यर्थी का प्रतिपरीक्षण स्पष्ट रूप से प्रकट करता है कि उसके बयान का पहला हिस्सा कि 'यह कहना गलत है कि जयराम अस्पताल के अलावा वह फिजियोथेरेपिस्ट के रूप में कहीं और प्रैक्टिस कर रही है', उस सुझाव का उत्तर है जो विद्वान विचारण न्यायालय के समक्ष

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा दिया गया था, जहाँ प्रत्यर्थी को यह सुझाव दिया गया था कि वह जयराम अस्पताल में अपने काम के अलावा निजी प्रैक्टिस कर रही थी। विद्वान विचारण न्यायालयों के समक्ष सामान्यतः यह देखा जाता है कि जब गवाह को ऐसे सुझाव दिए जाते हैं, तो गवाह अनिवार्य रूप से एक शब्द में उत्तर देता है कि 'गलत है' या 'नहीं' या 'हाँ' और उसके बाद, विद्वान विचारण न्यायालय उस उत्तर को प्रश्न से जोड़ते हुए टाइप करता है जैसा कि इस मामले में है, जहाँ यह दिया गया है कि 'यह कहना गलत है कि जयराम अस्पताल में उसके काम के अलावा उसकी कोई अन्य प्रैक्टिस है'। हालांकि, प्रत्यर्थी ने उसके बाद स्वेच्छा से बयान दिया कि वह बिल्कुल भी प्रैक्टिस नहीं कर रही है और उसने कभी कहीं काम नहीं किया है। वह धारा 21 के तहत शपथ पत्र के माध्यम से अपनी गवाही में कहती है कि पति और उसके परिवार के सदस्यों के षड्यंत्र के कारण उसकी नौकरी छूट गई।

12. विद्वान विचारण न्यायालय ने अपीलार्थी द्वारा उसके समक्ष रखे गए उन तर्कों की सही सराहना की है कि दस्तावेजों (प्रदर्शित सिद्ध दस्तावेजों या गवाही के रूप में) के माध्यम से कोई विश्वसनीय साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है, जो विद्वान विचारण न्यायालय को यह विचार करने के लिए विवश कर सके कि प्रत्यर्थी के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 195 के तहत अपराध का प्रथम दृष्टया मामला बनता है।

13. यहाँ यह उल्लेख करना भी प्रासंगिक है कि किसी सार्वजनिक प्राधिकरण या न्यायालय के समक्ष मामले में किए गए कदाचार / अपराध से उत्पन्न अपराध के लिए दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 340 के तहत कार्यवाही में, भारतीय दंड संहिता की धारा 195 के प्रवर्तन द्वारा तब तक संज्ञान वर्जित है जब तक कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 340 के तहत कार्यवाही के बाद संबंधित न्यायालय या सार्वजनिक कार्यालय द्वारा शिकायत नहीं की जाती है। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 340 के तहत कार्यवाही एक संक्षिप्त कार्यवाही है जहाँ संबंधित न्यायालय द्वारा एक जांच की जाती है जहाँ ऐसा झूठा साक्ष्य प्रस्तुत किया गया है / गवाही दी गई है, जिसे स्वयं को दो आधारों पर संतुष्ट करना होता है। पहला, यह कि प्रथम दृष्टया मामला बनता है कि अपराधी पक्ष ने न्यायिक कार्यवाही में ऐसा अपराध किया है और दूसरा, यह कि उक्त अपराध के लिए अपराधी पर मुकदमा चलाना न्याय के हित में समीचीन है। ऐसे अपराधों में, कोई निजी व्यक्ति पीड़ित नहीं होता बल्कि न्यायालय स्वयं पीड़ित होता है, क्योंकि अपराध न्यायिक कार्यवाही में किया जाता है। न्यायालय अपने विवेक से, अपराधी को प्रथम दृष्टया उत्तरदायी पाए जाने के बाद भी, ऐसा करने से बच सकता है यदि उसकी राय है कि कृत्य की गंभीरता और प्रभाव ऐसा नहीं है कि अपराधी पर मुकदमा चलाकर न्याय के उद्देश्यों की पूर्ति हो।

14. परिस्थितियों के दृष्टिगत, इस न्यायालय की राय है कि विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा दिया गया यह निष्कर्ष कि अपीलार्थी कोई भी विश्वसनीय सामग्री प्रस्तुत करने में सक्षम नहीं रहा है जो न्यायालय को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 340 के तहत राय बनाने हेतु भारतीय दंड संहिता की धारा 195 के अवरोध को शिथिल करने के लिए मजबूर करे कि रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्री के आधार पर प्रत्यर्थी पर मुकदमा चलाने की आवश्यकता है। इसलिए, यह न्यायालय महसूस करता है कि आक्षेपित आदेश में हस्तक्षेप करने की कोई आवश्यकता नहीं है। वर्तमान अपील खारिज की जाती है।

(विवेक सरन, न्यायमूर्ति) (अतुल श्रीधरन, न्यायमूर्ति)

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



मार्च 24, 2026

आर.के.जी.

Translated version. Not for Legal Use.

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"